

नाको समाचार



जुलाई अंक

अनुक्रमणिका

- 03 राष्ट्रीय स्तर पर लोकपाल का उन्मुखीकरण
- 04 ट्रांसजेंडर हेल्थ के संदर्भ में चिकित्सा पेशेवरों का सुग्राहीकरण: 'क्वेरेंसिया' में नाको की भागीदारी
- 05 सामुदायिक व्यवस्था का सुदृढीकरण: सामुदायिक जुड़ाव में एक आदर्श बदलाव
- 06 विगत वर्षों के दौरान कंडोम संवर्धन में परिवर्तन: भारत के अनुभव का साझाकरण
- 07 न्यू इंडिया@75 हेतु संगठन की तैयारी के पश्चात् राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण
- 07 महाविद्यालयों में 'सेहत केन्द्र' की स्थापना - बिहार एस.ए.सी.एस.
- 08 संयुक्त कार्य समूह की बैठक - सिक्किम एस.ए.सी.एस.
- 08 पुलिस प्रशिक्षुओं का सुग्राहीकरण - कर्नाटक एस.ए.पी.एस.
- 09 'मेघदूत पोस्टकार्ड': एच.आई.वी./एड्स पर जानकारी का संवर्धन - तमिलनाडु एस.ए.सी.एस.
- 10 नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस का अवलोकन

संरक्षक की कलम से

प्रिय पाठकों,

मैं नाको न्यूज़ के जुलाई संस्करण में आप सभी का स्वागत करता हूँ!



जुलाई, 2021 का महीना कार्यक्रम के लिए अत्यंत आकर्षक महीना रहा है। नाको ने एच.आई.वी. एवं एड्स (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 2017 के अनुसार राज्यों द्वारा नामित/नियुक्त लोकपाल की भूमिकाओं और कामकाज पर एक राष्ट्रीय स्तर के उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया। मुझे पूरा विश्वास है कि यह परामर्श कार्यक्रम राज्य स्तर पर लोकपाल की क्षमता निर्माण में सहायक रहा है।

हमने सामुदायिक प्रणाली सुदृढीकरण (सी.एस.एस.) पर सामुदायिक चर्चा और विचार-विमर्श के लिए राष्ट्रीय हितधारक परामर्श कार्यक्रम का भी आयोजन किया था। सामुदायिक प्रणाली सुदृढीकरण (सी.एस.एस.) कार्यक्रम 2030 तक एड्स को पूरी तरह से समाप्त करने हेतु विगत कुछ वर्षों में विचाराधीन रहा है और इसने अपनी प्रतिबद्धता दर्शाई है, और कार्यक्रम के सभी स्तरों पर सामुदायिक जुड़ाव, भागीदारी तथा अधिकारिता पर अधिक ध्यान देने की परिकल्पना भी की गई।

भारत का एड्स नियंत्रण कार्यक्रम अन्य देशों के लिए सीखने का मंच रहा है। यह हमें आगे बढ़ने वाले नए मॉडलों के बारे में नए विचारों को साझा करने का अवसर देता है। नाको ने हाल ही में प्रायोरिटी - पॉपुलेशन तक पहुँचने हेतु विभिन्न नेटवर्कों के ज़रिए रोकथाम के साधनों के वितरण को सुदृढ करने और कार्य योजना विकसित करने के लिए इंडोनेशिया और थाईलैंड के साथ बातचीत की है, जिसका उद्देश्य प्राथमिकता वाली आबादी के बीच इन रोकथाम के साधनों की उपलब्धता तथा पहुँच को बढ़ाकर वितरण में तेज़ी लाना और अनुकूलित करना था। मैं आशा करता हूँ की भारत के अनुभव दोनों देशों के लिए मददगार साबित होंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं आप सभी से कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने और इस बीमारी से लड़ने में हमारी मदद करने का अनुरोध करता हूँ।

मेरी शुभकामनाएँ,

आलोक सक्सेना
अपर सचिव एवं महानिदेशक (नाको)
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,
भारत सरकार

संपादक की कलम से



प्रिय पाठकों,

हमें नाको न्यूज़ का जुलाई संस्करण पेश करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है!

मुझे आप सभी को यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि नाको सभी राज्यों की एड्स नियंत्रण समितियों के साथ मिलकर इंडिया@75 की तैयारियों में जुटा हुआ है। नाको चरणबद्ध तरीके से एच.आई.वी. व एड्स, क्षय रोग तथा रक्तदान पर जागरूकता अभियान शुरू करेगा। इन जागरूकता अभियानों के ज़रिए स्कूलों, कॉलेजों और अन्य संस्थानों में रेड रिबन क्लब की ओर से कई तरह की गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य एच.आई.वी./टी.बी. की रोकथाम और सेवाओं के बारे में जानकारी देना, एच.आई.वी./एड्स तथा टी.बी. से पीड़ित लोगों के प्रति टैबू और भेदभाव को कम करने हेतु इस संक्रमण के बारे में लोगों में समझ विकसित करना और रक्तदान को प्रोत्साहित करना है।

मैं राज्य भर के 28 कॉलेजों में 'सेहत केंद्र' स्थापित करने हेतु बिहार एस.ए.सी.एस. के प्रयासों की सराहना करता हूँ। ये सेहत केंद्र कॉलेज के छात्रों के लिए उनकी स्वास्थ्य ज़रूरतों और अधिकारों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा, विचार-विमर्श और जागरूकता पैदा करने हेतु एक सुरक्षित स्थान के रूप में कार्य करेंगे। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इस पहल के ज़रिए बी.एस.ए.सी.एस. स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार (एस.एच.एस.बी.) और पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया (पी.एफ.आई.) को एक साथ लाया गया है। जब हम बहु-क्षेत्रीय सहयोग की बात करते हैं, तो हमारी परिकल्पना यही रहती है। मैं आप सभी से ऐसे और विकल्पों का पता लगाने का आग्रह करता हूँ ताकि बुनियादी साधन के सीमित होने पर भी अधिकतम उत्पादन आसानी से प्राप्त किया जा सके।

एक और अच्छी खबर सिक्किम राज्य से आई है, जहां हाल ही में विशेष रूप से एच.आई.वी./एड्स, मादक द्रव्यों के सेवन, क्षय रोग और किशोर शिक्षा कार्यक्रम से संबंधित युवा-केंद्रित कार्यक्रमों को लागू करते समय संबंधित विभाग, एन.जी.ओ. और एस.ए.सी.एस. के बीच तालमेल को बेहतर बनाने हेतु युवाओं पर एक संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई है।

राज्यों में टियर 2 और टियर 3 शहरों तक पहुंचने के लिए एस.ए.सी.एस. ने हमेशा ही प्रयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाया है। यह हमें नए हस्तक्षेपों का पता लगाने की प्रेरणा भी देता है। ऐसी ही एक पहल तमिलनाडु राज्य में शुरू हुई है जिसे टी.एन.एस.ए.सी.एस. ने डाक सेवा विभाग के सहयोग से संपन्न किया है। इस पहल के तहत, 'पंच पाटी' नामक शुभंकर को एच.आई.वी./एड्स की नेशनल टोल फ्री हेल्प लाइन : 1097 पर जागरूकता संदेश देने वाले एक लाख से अधिक 'मेघदूत पोस्टकार्ड' पर मुद्रित किया गया। ये पोस्टकार्ड एच.आई.वी. और एड्स के साथ जी रहे लोगों के लिए उपलब्ध विभिन्न सेवाओं को बढ़ावा देने हेतु मुफ्त में वितरित किए गए।

अपने इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अब राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर मौजूद अपने सभी सहयोगियों, साथी अधिकारियों और अधीनस्थों को अलविदा कहता हूँ, क्योंकि मेरी सेवाएं और एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के साथ लंबा जुड़ाव 31 अगस्त, 2021 को मेरी सेवानिवृत्ति के साथ समाप्त हो रहा है। मैं सेवानिवृत्ति के बाद सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी गतिविधि में स्वैच्छिक सेवा देने के लिए तत्पर हूँ और मुझे ऐसा करने में प्रसन्नता होगी। मैं ईश्वर से आप सभी की सुरक्षा और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ।

आप सभी को मेरी शुभकामनाएँ।

डॉ. नरेश गोयल,
डी.डी.जी. (आई.ई.सी. एवं एम.एस.), नाको
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,
भारत सरकार

राष्ट्रीय स्तर पर लोकपाल का उन्मुखीकरण

राज्य एड्स नियंत्रण समितियों की स्थापना की तत्काल ज़रूरत का संज्ञान लेते हुए, नाको ने 9 जुलाई, 2021 को श्री आलोक सक्सेना, अपर सचिव एवं महानिदेशक, नाको की अध्यक्षता में लोकपाल की भूमिका एवं कामकाज पर राष्ट्रीय स्तर के पहले उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस उन्मुखीकरण कार्यक्रम में 16 राज्यों यानि छत्तीसगढ़, पंजाब, मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, गोवा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, तमिलनाडु, गुजरात, ओडिशा और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुल 31

लोकपाल शामिल हुए।

इस उन्मुखीकरण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोकपाल को एच.आई.वी. एवं एड्स (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 2017 के तहत उन्हें सौंपे गए कर्तव्यों से अवगत कराना था; ताकि वो पी.एल.एच.आई.वी. के कानूनी अधिकारों को पूरी तरह से समझ सकें और इस अधिनियम के तहत निषिद्ध किसी भी तरह के उल्लंघन की पहचान कर सकें।

पृष्ठभूमि

एच.आई.वी. और एड्स (रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 2017 इसमें प्रावधानों (धारा 3 तथा स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने) के किसी भी तरह के उल्लंघन की जांच हेतु संबंधित राज्य सरकारों द्वारा लोकपाल की नियुक्ति का प्रावधान करता है। एच.आई.वी. और एड्स (रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 2017 के खंड X के तहत धारा 23, 24, 25, 26, 27, 28 और धारा 38 लोकपाल को प्रदत्त अधिकारों से संबंधित है, जिसमें लोकपाल को प्रदान की गई शक्तियों, शिकायत की प्रक्रिया और लोकपाल के दिशा-निर्देशों का विवरण दिया गया है।

मुख्य बातें

- ▶ जे.वी.आर. प्रसाद राव, विशेष सलाहकार, डब्ल्यूएचओ एसईएआरओ ने संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नियम बनाकर और केंद्र सरकार द्वारा दिशानिर्देशों की अधिसूचना के ज़रिए केंद्रीय कानून के महत्व को सामने रखते हुए कार्यक्रम में शामिल राज्यों के प्रतिनिधियों को संबोधित किया।
- ▶ श्री आलोक सक्सेना, अपर सचिव एवं महानिदेशक, नाको ने एच.आई.वी. और एड्स (रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 2017 की विधायी मंजूरी पर रूपरेखा पेश की। उन्होंने एच.आई.वी. और एड्स से जुड़े टैबू और भेदभाव की व्यापकता तथा इससे निपटने के लिए मज़बूत शिकायत निवारण तंत्र बनाने की आवश्यकता पर बल दिया।
- ▶ डॉ. राजेश राणा, राष्ट्रीय सलाहकार (आई.ई.सी. एंड एमएस) ने एच.आई.वी. और एड्स (रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 2017 के तहत किए गए प्रमुख प्रावधानों पर जानकारी दी, जिसमें विभिन्न तरह के भेदभाव से निपटने से जुड़े प्रावधान, इन्फोर्मेट कंसेंट, एच.आई.वी. की स्थिति का खुलासा न करने का अधिकार, डेटा

गोपनीयता, निवास का अधिकार, बड़े भाई-बहनों की संरक्षकता और कानूनी कार्यवाही में पहचान की गोपनीयता जैसे विषय शामिल थे।

- ▶ गरिमा शर्मा, एपीडी, जीएफएटीएम-नाको प्रोजेक्ट, शेयर इंडिया ने मुख्य रूप से राज्य के नियमों के आधार पर लोकपाल की सेवा शर्तों पर एक प्रस्तुति दी। उन्होंने लोकपाल के कामकाज के महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे, शिकायतों की जांच करने के तरीके, रिकॉर्ड बनाए रखने की आवश्यकता और शिकायत दर्ज कराने के तरीके आदि पर बात की।

- ▶ कार्यक्रम के समापन के दौरान, लोकपाल को मिलने वाली शिकायतों के व्यावहारिक उदाहरणों पर चर्चा करते हुए एक केस स्टडी पेश की गई। कार्यक्रम के अंत में, इस संदर्भ में पूछे गए कुछ सवालों का जवाब भी दिया गया। नाको की ओर से राज्यों से लोकपाल से संबंधित वेबसाइट बनाने का आग्रह किया गया। और राज्यों द्वारा लोकपाल नियुक्त/नामित किए जाने के पश्चात् लोकपाल उन्मुखीकरण के दूसरे दौर का आयोजन किया जाएगा।



ट्रांसजेंडर हेल्थ के संदर्भ में चिकित्सा पेशेवरों का सुग्राहीकरण: 'क्वैरेंसिया' में नाको की भागीदारी

चिकित्सा पेशेवरों का सुग्राहीकरण भारत में ट्रांसजेंडर (टी.जी.) समुदाय के लोगों द्वारा सामना की जाने वाली स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत में ट्रांसजेंडर (टी.जी.) समुदाय की स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरतों का संज्ञान लेते हुए, नाको वर्ल्ड प्रोफेशनल एसोसिएशन फॉर ट्रांसजेंडर हेल्थ (डब्ल्यू.पी.ए.टी.एच.), और एसोसिएशन फॉर ट्रांसजेंडर हेल्थ (ए.टी.एच.आई.) जैसे कुछ भारतीय और वैश्विक पेशेवर संगठनों के साथ मिलकर काम कर रहा है। इसी प्रयास में, डॉ. शोभिनी राजन, डी.डी.जी., नाको ने 24 जुलाई, 2021 को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर आयोजित 'डिमिस्टीफाइंग जेंडर: फोस्टरिंग जेंडर-फ्रेंडली हेल्थकेयर' नामक एक वेबिनार श्रृंखला में हिस्सा लिया। इस वेबिनार का आयोजन डब्ल्यू.पी.ए.टी.एच. और आईएपी (इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स) के सहयोग से

लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज (एल.एच.एम.सी.) के मेडिकल छात्रों, 'क्वैरेंसिया', और एल.एच.एम.सी. का किशोर स्वास्थ्य डब्ल्यू.एच.ओ. स्वास्थ्य सहयोग केंद्र द्वारा किया गया था। वेबिनार में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त वक्ताओं ने हिस्सा लिया और भारत तथा वैश्विक स्तर पर ट्रांसजेंडर स्वास्थ्य देखभाल से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर भाषण दिया।

डॉ. शोभिनी राजन, डी.डी.जी., नाको ने अपने भाषण के दौरान एच.आई.वी./एड्स और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरतों के साथ-साथ ट्रांसजेंडर समुदाय को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने हेतु एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने में नाको की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने भारत में

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को लिंग संवेदनशील चिकित्सा देखभाल पर चिकित्सा पाठ्यक्रम को अपनाने और मेडिकल छात्रों को संवेदनशील बनाने हेतु राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद के साथ नाको के जुड़ाव से अवगत कराया।

इस वेबिनार में मेडिकल छात्र, मेडिकल कॉलेजों के शिक्षकों, स्वास्थ्य सेवा प्रदाता (मेडिकल, नर्सिंग व पैरा-मेडिकल), सामाजिक कार्यकर्ता और सामाजिक विज्ञान के छात्रों और समुदाय के अन्य सदस्यों सहित 300 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। वेबिनार में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दर्शक भाग ले सकें और वक्ताओं के साथ बातचीत कर सकें, इसके लिए इसे नाको के यूट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रीम किया गया था। इस वेबिनार में शामिल वक्ताओं और सत्रों को लेकर प्रतिभागियों के साथ-साथ सोशल मीडिया पर बहुत अधिक रुचि देखने को मिली।



सामुदायिक व्यवस्था का सुदृढीकरण: सामुदायिक जुड़ाव में एक आदर्श बदलाव

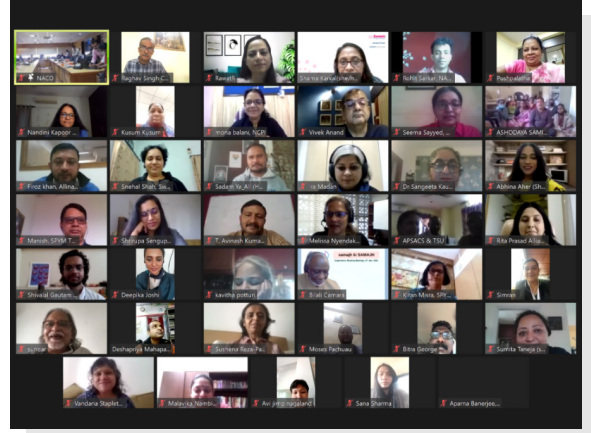
राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (एन.ए.सी.ओ.) के तहत राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (एन.ए.सी.पी.) की स्थापना के बाद से ही, यह समुदाय भारत में एच.आई.वी./एड्स प्रतिक्रिया का केंद्र रहा है। कार्यक्रम के ज़रिए निरंतर परामर्श मिलता रहे और प्रतिक्रिया को सुदृढ बनाने के लिए उनसे जुड़ाव बना रहे इसके लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम में प्रमुख आबादी के साथ-साथ पी.एल.एच.आई.वी. को इसकी प्रतिक्रिया के केंद्र में रखा गया है, इसलिए नाको द्वारा रोकथाम, उपचार और देखभाल हेतु अपनाई गई रणनीति से बड़ा बदलाव आया है।

विगत कुछ वर्षों से सामुदायिक प्रणाली का सुदृढीकरण (सी.एस.एस.) विचाराधीन है और 2030 तक एड्स के उन्मूलन की प्रतिबद्धता के साथ, कार्यक्रम के सभी स्तरों पर सामुदायिक जुड़ाव, भागीदारी और अधिकार पर अधिक ज़ोर देने की कल्पना की गई है। इस संदर्भ में, राष्ट्रीय सी.एस.एस. ढांचे के विकास में आदान और साथ ही सी.एल.एम. को पायलट प्रारूप में शुरू करने के लिए महत्वपूर्ण प्रक्रिया तथा साधन प्रदान करने हेतु सी.एस.एस. पर सामुदायिक चर्चा एवं विचार-विमर्श के लिए नाको

ने यू.एन.एड्स के सहयोग से फरवरी 2021 में एक राष्ट्रीय हितधारक परामर्श का आयोजन किया। नाको ने विकास भागीदारों और सामुदायिक प्रतिनिधियों सहित प्रमुख हितधारकों को इस परामर्श में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सी.एस.एस. के कार्यान्वयन और सी.एल.एम. के रोल आउट में ज़िला, राज्य और राष्ट्रीय कारकों और समुदाय (प्रमुख आबादी और पी.एल.एच.आई.वी.) के बीच एक मज़बूत साझेदारी बनाते हुए समुदाय को केन्द्र में रखा जाए।

राष्ट्रीय परामर्श से मिली सिफारिशों के अनुसार, नाको ने यू.एन.एड्स को राष्ट्रीय कार्य समूह स्थापित करने हेतु आमंत्रित किया, जिसमें युवा प्रतिनिधियों सहित समुदायों के सदस्य भी शामिल हैं। कार्य समूह का मुख्य उद्देश्य भारत में सी.एस.एस. के कार्यान्वयन का मार्गदर्शन और निगरानी करना और साथ ही राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के रूप में अपनाने के लिए फ्रेमवर्क, मानक संचालन प्रक्रियाओं को लागू करने हेतु नाको को सिफारिशें करना, और साथ-साथ सी.एस.एस. कार्यान्वयन और सामुदायिक नेतृत्व निगरानी (सी.एल.एम.) पर निगरानी और आदान प्रदान करना है।

सी.एस.एस. के अनिवार्य घटकों में से एक के रूप में, सामुदायिक नेतृत्व निगरानी (सी.एल.एम.) गुणवत्ता सेवाओं और न्यूनतम नीतियों तथा मानकों के कार्यान्वयन पर शुरुआती दृष्टिकोण प्रदान करता है। नाको ज़मीनी स्तर और सेवा वितरण केन्द्रों पर एच.आर.जी. और पी.एल.एच.आई.वी. के रणनीतिक जुड़ाव हेतु एक व्यवहार्य तंत्र के रूप में सी.एल.एम. को संस्थागत बनाने का प्रयास कर रहा है। प्रमुख आबादी और रोकथाम प्रतिक्रिया पर बल देते हुए मुख्य ध्यान रोकथाम तथा उपचार दोनों में परिणाम हासिल करने और साथ ही एच.आई.वी. पीड़ित लोगों और उपचार कार्यक्रमों के प्रतिधारण पर रहा है।

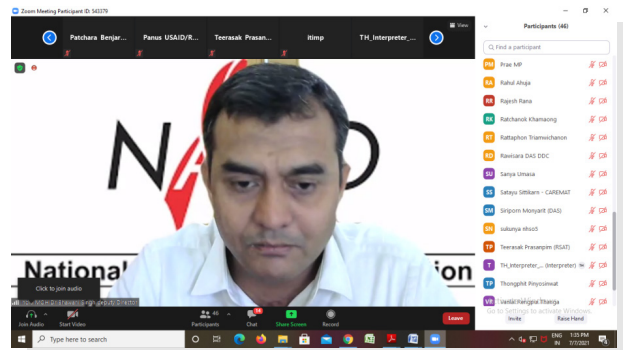


विगत वर्षों के दौरान कंडोम संवर्धन में परिवर्तन: भारत के अनुभव का साझाकरण

प्राथमिकता वाली आबादी और स्थानों तक पहुंच हेतु कंडोम वितरण नेटवर्क के अनुकूलन के लिए नाको को इंडोनेशिया और थाईलैंड के साथ एक संवाद में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया गया था, जिसका आयोजन वर्चुअल प्रारूप में 7 जुलाई, 2021 को किया गया था। इस बैठक का उद्देश्य नए तरीकों पर नए विचार साझा करने हेतु इन जगहों पर कार्यान्वित अन्य कंडोम कार्यक्रमों से सीखे गए व्यावहारिक अनुभव और सबक को रेखांकित करना, और प्राथमिकता वाली आबादी के बीच इसकी उपलब्धता और पहुंच बढ़ाकर कंडोम वितरण में तेज़ी लाने और इसे अनुकूलित करने हेतु कार्य योजना तैयार करना था। इस बैठक के लक्षित भागीदार रोग नियंत्रण विभाग/सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्रालय, एन.एच.एस.ओ., यू.एस.ए.आई.डी./पी.ई.पी.एफ.ए.आर., एफ.एच.आई.-360 राष्ट्रीय प्रबंधक एवं ग्लोबल फंड के पीआर, समुदाय-आधारित संगठन, एन.जी.ओ. और यू.एन.ए.आई.डी. टीम के प्रतिनिधि थे।

डॉ. भवानी सिंह, उप निदेशक-टीआई, नाको ने बैठक में नाको की ओर से हिस्सा लिया और एन.ए.सी.पी. I से एन.ए.सी.पी. IV और उससे पश्चात् कंडोम कार्यक्रम के विकास पर प्रकाश डाला। उन्होंने कंडोम संवर्धन दृष्टिकोण, एन.ए.सी.पी. के तहत उपलब्धता और मांग का सृजन, मुफ्त कंडोम आपूर्ति चैनल, प्रक्रिया पहल (मांग व

आपूर्ति) और चुनौतियों, सामाजिक विपणन, वितरण चैनल सीएसएमपी, कार्यान्वयन दृष्टिकोण, नाको सीएसएमपी के डेटा सत्यापन तंत्र, निगरानी व मूल्यांकन, संचार अभियान के विकास, संचार चैनल, मास मीडिया अभियान और कार्यक्रम प्रभाव-गुणवत्ता आश्वासन व मूल्यांकन, व्यवहार सर्वेक्षण आदि के बारे में बात की।



थाईलैंड में यू.एन.एड्स के निर्देशक ने बैठक के दौरान, प्राथमिकता वाली आबादी तक मुफ्त कंडोम की पहुंच सुनिश्चित करने की भारत की प्रतिबद्धता की सराहना की। इसके अलावा, उन्होंने नाको द्वारा अपने ज़मीनी और व्यावहारिक अनुभवों को साझा करने की सराहना की और भविष्य में सहयोग जारी रखने की इच्छा व्यक्त की।

न्यू इंडिया@75 हेतु संगठन की तैयारी के पश्चात् राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण

देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत सरकार न्यू इंडिया@75 अवधारणा को लेकर बहुत तत्पर है, जिसका उद्देश्य प्रणाली की दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार लाना है। न्यू इंडिया@75 के विकास में अपना योगदान करने के लिए, राष्ट्रीय एड्स संगठन (नाको) एक जागरूकता अभियान शुरू करेगा। इन जागरूकता अभियानों के ज़रिए स्कूलों और कॉलेजों में बने रेड रिबन क्लबों द्वारा कई गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। ये अभियान एच.आई.वी./एड्स और टी.बी. के बारे में जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ रक्तदान को बढ़ावा देने पर आधारित होंगे।

इन अभियानों का उद्देश्य कार्यक्रम के निम्न उद्देश्यों को हासिल करना है:

- ▶ एच.आई.वी./टी.बी. से संबंधित रोकथाम एवं सेवाओं पर सूचना का प्रसार;
- ▶ एच.आई.वी./एड्स और टी.बी. से पीड़ित लोगों के प्रति कलंक और भेदभाव को कम करने हेतु संक्रमण से संबंधित जानकारी में सुधार करना;
- ▶ प्रत्येक राज्य के 25 पब्लिक स्कूलों और विश्वविद्यालयों की

भागीदारी से युवाओं में रक्तदान को प्रोत्साहित करना। नाको को उम्मीद है कि इन अभियानों के ज़रिए हम देश भर के कम से कम 7.5 लाख छात्रों तक पहुंच सकेंगे। इन अभियानों को बनाने और संचालित करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य और क्षेत्रीय स्तर पर समितियों का गठन किया गया है। इन सभी समितियों को अभियान को जल्द से जल्द शुरू और निष्पादित करना है।

**New
India @ 75**

**EDUCATED YOUTH
EDUCATED NATION**



महाविद्यालयों में 'सेहत केन्द्र' की स्थापना - बिहार एस.ए.सी.एस.

बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति (बी.एस.ए.सी.एस.) ने राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार (एस.एच.एस.बी.) और पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया (पी.एफ.आई.) के सहयोग से बिहार के 28 कॉलेजों में 'सेहत केंद्र' की स्थापना की है। इन सेहत केंद्रों का मूल उद्देश्य कॉलेज के छात्रों को अपनी स्वास्थ्य ज़रूरतों और अधिकारों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा, विचार-विमर्श और जागरूकता फैलाने

हेतु एक सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराना है। समस्याओं, खतरनाक और असुरक्षित स्थितियों से निपटने के लिए सूचना और समर्थन तंत्र की कमी की वजह से युवाओं की यौन और प्रजनन स्वास्थ्य की सही जानकारी, शादी की सही उम्र, गर्भनिरोधक का विकल्प, मानसिक स्वास्थ्य, लिंग, मादक द्रव्यों के सेवन आदि जैसे स्वास्थ्य मुद्दों पर सही व सटीक जानकारी तक पहुंच सीमित है।

ये 'सेहत केंद्र' रेड रिबन क्लब के दायरे में काम करेंगे, जो सहकर्मी शिक्षकों द्वारा समर्थित है। सेहत केंद्र की स्थापना के उद्देश्य निम्नवत् हैं:

- ▶ यौन और प्रजनन स्वास्थ्य पर सटीक जानकारी तक पहुंच को बढ़ावा देना
- ▶ किशोरों एवं युवाओं से जुड़े मुद्दों पर खुली चर्चा
- ▶ लैंगिक समानता और जीवन कौशल के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना
- ▶ स्वास्थ्य से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे पोषण, मानसिक

स्वास्थ्य, मादक द्रव्यों के सेवन, गैर-संचारी रोग, एच.आई.वी.-एड्स, रक्तदान का महत्व तथा कम उम्र में विवाह और हिंसा व लिंग आधारित भेदभाव जैसे सामाजिक मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करना।



संयुक्त कार्य समूह की बैठक - सिक्किम एस.ए.सी.एस.

सिक्किम एस.ए.सी.एस. ने 26 जुलाई, 2021 को संयुक्त कार्य समूह की बैठक का आयोजन किया था। इस बैठक में शिक्षा विभाग, युवा कार्यक्रम और खेल विभाग, एन.वाई.के., एन.ए.सी.एस., एस.सी.ई.आर.टी., सिक्किम के स्वैच्छिक रक्त दाता संघ के प्रतिनिधियों और एस.ए.सी.एस. अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक का मुख्य एजेंडा युवा केंद्रित कार्यक्रमों, विशेष रूप से एच.आई.वी. / एड्स, मादक द्रव्यों के सेवन, तपेदिक, किशोर शिक्षा जैसे कार्यक्रम आदि को लागू करते हुए संबंधित विभाग, एनजीओ और एस.ए.सी.एस. के बीच तालमेल बेहतर बनाना था।



पुलिस प्रशिक्षुओं का सुग्राहीकरण - कर्नाटक एस.ए.पी.एस.



21 जुलाई, 2021 को के.एस.ए.पी.एस. ने ज़िला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और जीवमृत ब्लड बैंक, लायंस इंस्टीट्यूट के सहयोग से कर्नाटक के रामनगर ज़िले के चन्नापटना में पुलिस प्रशिक्षुओं के लिए एक प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में लगभग 740 पुलिस प्रशिक्षण अधिकारियों, कर्मचारियों और पुलिस प्रशिक्षुओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान कई सवाल पूछे गए और उनका विधिवत जवाब दिया गया। इसके बाद शपथ ग्रहण समारोह के साथ इस सत्र का समापन हुआ।

रामनगर डी.ए.पी.सी.यू. द्वारा आयोजित सत्र के दौरान निम्नलिखित विषयों पर चर्चा हुई:

- ▶ एच.आई.वी./एड्स पर संदेश
- ▶ एच.आई.वी. के साथ जी रहे लोगों के प्रति टैबू और भेदभाव

- ▶ एच.आई.वी. और एड्स (रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 2017 का महत्व
- ▶ जोखिम में आने वाली आबादी
- ▶ संक्रमित और प्रभावित आबादी हेतु उपलब्ध सामाजिक सुरक्षा योजनाएं
- ▶ रक्तदान का महत्व



"मेघदूत पोस्टकार्ड": एच.आई.वी./एड्स पर जानकारी का संवर्धन - तमिलनाडु एस.ए.सी.एस.

तमिलनाडु स्टेट राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी ने भारतीय डाक सेवा विभाग के सहयोग से नाको एवं टी.एन.एस.ए.सी.एस. का मुद्रित पोस्टकार्ड जारी किया, जो कंडोम संवर्धन से संबंधित जागरूकता संदेशों पर प्रकाश डालता है।

इसे सुविधाजनक बनाने हेतु, इंडिया पोस्ट ने 100,000 "मेघदूत पोस्टकार्ड" मुद्रित किए और 19 जुलाई, 2021 को जारी किए। ये पोस्टकार्ड डाक सेवाओं के ज़रिए राज्य के सभी अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त बांटे गए। इस मुहिम के पीछे का मुख्य उद्देश्य

एन.ए.सी.पी. के तहत शुरु की गई पहल एवं प्रावधानों सहित एच.आई.वी./एड्स जागरूकता को बढ़ावा देना था।

तमिलनाडु एस.ए.सी.एस. ने 'पंच पाटी' नामक एक मुद्रित छवि को पेश किया है, जिसपर मुफ्त में उपलब्ध विभिन्न सेवाओं को बढ़ावा देने हेतु 'मेघदूत पोस्टकार्ड' के बाईं ओर एच.आई.वी./एड्स की नेशनल टोल फ्री हेल्प लाइन नंबर: 1097 लिखा हुआ है।



नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस का अवलोकन

नशीली दवाओं के दुरुपयोग (आई.डी.डी.ए.) और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 26 जून को मनाया जाता है। यह मादक द्रव्यों के सेवन के साथ-साथ नशीली दवाओं के अवैध व्यापार से निपटने हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रस्तावित एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है।

आई.डी.डी.ए. का इस वर्ष का विषय 'शेयर ड्रग्स फैक्ट्स टू सेव लाइव्स' था। इस विषय का उद्देश्य गलत सूचनाओं का मुकाबला करना और ड्रग्स पर सही जानकारी - ड्रग्स की वैश्विक समस्या से निपटने हेतु स्वास्थ्य जोखिम और समाधान से लेकर

साक्ष्य-आधारित रोकथाम, उपचार और देखभाल तक - के साझाकरण को बढ़ावा देना है। कोविड-19 ने स्वास्थ्य पर अभूतपूर्व जन जागरूकता, स्वस्थ रहने के लिए सुरक्षात्मक उपाय और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक दूसरे की रक्षा करना सिखाया है।

देश भर की राज्य एड्स नियंत्रण समितियों ने इस मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु ब्लॉक और ज़िला स्तर पर कई ऑनलाइन और ऑफलाइन गतिविधियों का आयोजन किया।

राज्य स्तर पर आयोजित कुछ गतिविधियों की जानकारी यहां दी गई है:



अंडमान और निकोबार एड्स नियंत्रण सोसाइटी ने एक स्थानीय समाचार पत्र के एक चौथाई पेज पर विज्ञापन छपा

अंडमान और निकोबार एस.ए.सी.एस. द्वारा विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों पर बैनर और होर्डिंग लगाई गई



मेघालय में विभिन्न स्थानों पर टी.आई. एन.जी.ओ. द्वारा जागरूकता सत्र का आयोजन



सत्यमेव जयते
Ministry of Health & Family Welfare
Government of India

NACO

National AIDS Control Organisation
India's Voice against AIDS
Ministry of Health & Family Welfare, Government of India
www.naco.gov.in

अधिकार उपचार अवसर

संरक्षक: श्री आलोक सक्सेना, अपर सचिव एवं महानिदेशक, नाको, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

निदेशक: सुश्री निधि केसरवानी, निदेशक नाको, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

संपादक: डॉ. नरेश गोयल, डीडीजी नाको, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

संपादकीय पैनल: डॉ. ए. के. पुरी (डी.डी.जी.), डॉ. शोबिनी राजन (डी.डी.जी.), डॉ. राजेश राणा (राष्ट्रीय परामर्शदाता), नाको, डॉ. ज्योतिका चीमा (परामर्शदाता) नाको, शेयर इंडिया टीम

नाको ई-न्यूजलेटर राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का डिजिटल प्रकाशन है।

छठी और नौवीं मंजिल, चंद्रलोक बिल्डिंग, 36-जनपथ, नई दिल्ली – 110001 दूरभाष: 011-43509999, फ़ैक्स: 011-23731746

हमारी वेबसाइट पर जाएं: www.naco.gov.in

संपादन, डिजाइन एवं उत्पादन: विजुअल हाउस, ई-मेल: tvh@thevisualhouse.in

आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृपया हमें nacoindianews@gmail.com पर लिखें।

@NACOINDIA

@NACOINDIA

@NACO_INDIA

@NACOINDIA

सर्व लोगों, सुर-सुर जति



Download NACO AIDS APP

Supported By |